

संपादकीय

दोनों का फायदा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत की यात्रा पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यह यात्रा जुलाई में पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा के बाद हुई है, जहां दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। स्टार्मर, जो उद्योग जगत के बड़े नामों के साथ भारत आए, ने नई दिल्ली के साथ साझेदारी को 'ग्रोथ का लॉन्चपैड' बताया, जबकि पीएम मोदी ने ब्रिटेन को 'स्वाभाविक साझेदार' कहा। यह मुलाकात दो महीने पहले हुए विस्तृत आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) को जल्द लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए एक जॉइंट कमिटी बनाने का ऐलान किया गया है।

इस व्यापार समझौते से दोनों देशों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। ब्रिटेन से भारत आने वाले सामानों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% हो जाएगा, वहीं भारत से ब्रिटेन निर्यात होने वाले 99% उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस डील से व्यापारियों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वर्तमान में दोनों देशों के बीच लगभग 56 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह सहयोग ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय उद्योग, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर, अमेरिकी टैरिफ के कारण दबाव में है। आशंका है कि चीन और बांग्लादेश पर कम टैरिफ के कारण भारत के टेक्सटाइल निर्यात में अगले साल 10% तक की गिरावट आ सकती है। ब्रिटेन के साथ हुई यह डील इस संभावित नुकसान को कम करने में मददगार साबित होगी।

स्टार्मर के दौर ने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, शिक्षा, निवेश, स्वास्थ्य और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। एक बड़ी घोषणा यह है कि ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगे। यह उन भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो अमेरिका की वीजा नीतियों के कारण विदेश में पढ़ाई के अवसरों को लेकर चिंतित थे। अपने ही देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने से रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर दोनों ही इन द्विपक्षीय समझौतों को ऐतिहासिक मान रहे हैं, जिसका मुख्य कारण मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों हैं। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच, इन मुलाकातों ने दोनों देशों को नए विकल्प दिए हैं। ये नए विकल्प उन्हें अमेरिका के साथ बातचीत करते समय एक मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। यह साझेदारी न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी। यह दिखाता है कि कैसे देश आपसी सहयोग से वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने नागरिकों के लिए बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं। इस तरह की साझेदारी भविष्य में और भी मजबूत होने की उम्मीद है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी।

देश-दुनिया की निगाहे माइनिंग सेक्टर तो एग्रेसिव मोड पर राजस्थान

अमेरिका कमी कनाडा को अमेरिका का राज्य ही बनाने में जुटा है तो यूक्रेन की खनिज संपदा अपने नाम करवाने या रुस पर दबाव बनाने के पीछे धरती के गर्भ में समाई खनिज संपदा ही है। खनिज संपदा पर आज दुनिया के देशों की नजर है।

प्रेरणा



क्रोध से उत्पन्न विनाश और धैर्य का अमर संदेश

प्राचीन काल में एक गुरुकुल था, जहाँ एक महान आचार्य अपने शिष्यों को न केवल वेद और शास्त्रों का ज्ञान देते थे, बल्कि जीवन की वास्तविक साधना — संयम और धैर्य — भी सिखाते थे। उनका कहना था कि जितना आवश्यक ज्ञान है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है "स्वयं पर विजय।" वे कहा करते — "जो अपने मन और क्रोध को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है।" एक दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी गाँव से भागते हुए कुछ लोग आए और चिल्लाने लगे — "गुरुदेव! गाँव में भारी हंगामा हो गया है, एक व्यापारी ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर एक गरीब ब्राह्मण को पीटा है। लोग आपसे न्याय की विनती कर रहे हैं।" गुरु तुरंत गाँव पहुँचे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण रक्त से लथपथ पड़ा है और व्यापारी क्रोध में काँप रहा है। गुरु ने व्यापारी से पूछा — "तुमने बिना प्रमाण के इस ब्राह्मण को क्यों मारा?" व्यापारी बोला — "मुझे गुस्सा आ गया था, गुरुदेव! मैंने सोचा इसने मेरे घर से वस्तु चुराई है।" गुरु ने शांत स्वर में कहा — "जब क्रोध आता है, तब मनुष्य सोचता नहीं, केवल विनाश करता है। देखो, तुमने क्या कर दिया। जिस पर शक किया, वह निर्दोष निकला, और अब तुम्हारा अपना सम्मान, तुम्हारी आत्मा, दोनों धायल हो चुके हैं।" व्यापारी रो पड़ा और बोला — "गुरुदेव, मैं उस क्षण में जैसे अंधा हो गया था।" गुरु बोले — "यह तो क्रोध की विशेषता है — यह पहले विवेक को



खा जाता है, फिर व्यक्ति को दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी संकट बना देता है।" फिर गुरु ने अपने शिष्यों से कहा — "क्रोध किसी बाहरी शत्रु से भी अधिक भयानक है। बाहरी शत्रु केवल शरीर को हानि पहुँचाता है, पर क्रोध आत्मा की ज्योति को बुझा देता है। क्रोध में व्यक्ति अपना निर्णय खो देता है, वह सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। जब मनुष्य अपने ही विवेक से दूर हो जाता है, तब उसका पतन निश्चित है।" गुरु ने आगे कहा — "क्रोध का मूल भय है। जब हम किसी स्थिति से डरते हैं, तो भीतर एक से पहले अपने विचारों को बाँधना चाहिए। जब मन



उच्चस्तरीय परियोजना मोनेट्रिंग इकाई (पीएमयू) का गठन किया है। माना जा रहा है कि प्रदेश में क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिजों के साथ ही प्रधान व अप्रधान खनिजों के विपुल भण्डारों को देखते हुए पीएमयू के गठन से खनिज क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाया जाएगा। इससे खानों जल्दी परिचालन आने के साथ ही निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वैसे भी आने वाले समय में माइनिंग सेक्टर की भूमिका में बड़ा बदलाव आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रप्रति ट्रंप की छटपटाहट से इसे आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिका कभी कनाडा को अमेरिका का राज्य ही बनाने में जुटा है तो यूक्रेन की खनिज संपदा अपने नाम करवाने या रुस पर दबाव बनाने के पीछे धरती के गर्भ में समाई खनिज संपदा ही है। खनिज संपदा पर आज दुनिया के देशों की नजर है। चीन के वर्चस्व का बड़ा कारण उसका आरईई सहित खनिज संपदा पर एकाधिकार ही है और आज चीन के इस वर्चस्व को कम करने में ही जुटे हुए हैं। खैर यह विषयांतर होगा पर

एक बात साफ है कि माइनिंग सेक्टर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व व मार्गदर्शन में तेजी से काम होने लगा है और राजस्थान ऑक्शन सहित रेवेन्यू अर्जन विकास दर आदि में अक्वल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में विपुल संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को देश में अग्रणी राज्य बनाने पर जोर देते रहे हैं। नई खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, रिसर्च में सहायता प्रावधान, एमनेस्टी योजना सहित प्रक्रिया के सरलीकरण और खनन क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। पीएमयू के गठन के साथ ही खनन क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों को 7 सेक्टरों में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सचिव माइन्स टी रविकान्त का मानना है कि सभी क्षेत्रों में समन्वित व तेजी से विकास के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए पीएमयू का गठन किया गया है जिससे योजनावद्ध तरीके से तेजी से आगे बढ़ा जा सके। एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन, शीघ्र परिचालन, रिसर्च एवं डवलपमेंट,

जीरो लॉस माइनिंग, इकोटूरिज्म की संभावनाओं, पेपरलेस सहित विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है। विभाग के वरिष्ठ व विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। खनिज क्षेत्र से जुड़े 7 प्रमुख सेक्टरों में से पहले एक्सप्लोरेशन व ऑक्शन का बनाया गया है। इस दल द्वारा कोमोडिटी, मिनरल ग्रेड, खनन के प्रकार सहित विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करेगी। यह दल जीएसआई सहित तकनीकी विशेषज्ञों से समन्वय बनाते हुए एक्सप्लोरेशन से ऑक्शन आदि संबंधित कार्यों को और अधिक प्रभावी गति दी जा सकेगी। इसी तरह से ऑक्शन किये गये माइजर और मिनरल ब्लॉकों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए आवश्यक अनुमतियाँ दिलाने में सहयोग के साथ ही शीघ्र परिचालन में लाने का कार्य करेगी। विभाग का जोर खनन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाने और राजस्व में किसी भी तरह की छीजत को रोकना भी है और इसके लिए एक दल को मोनेट्रिंग सहित आवश्यक सभी जिम्मेदारियों दी गई है। डीएमएफटी के कार्य को गति देने और राशि के बेहतर उपयोग की मोनेट्रिंग की जिम्मेदारी सौंपते हुए डीएमएफटी फण्ड के अन्य प्रदेशों में उपयोग को लेकर अध्ययन सहित योजना, क्रियान्वयन व मोनेट्रिंग का फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया है। राज्य सरकार का सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर रहने के साथ ही बदलते परिवेश में यह आवश्यक भी हो गया है। सस्टेनेबल माइनिंग और ऑटोमेशन और तकनीक सेक्टर दल द्वारा स्टार

रेंटिंग, बंद व कार्य नहीं कर रही खानों में इको टूरिज्म की संभावनाओं व क्रियान्वयन, डम्प ओवरवर्डन आदि के रिसाईक्लिंग व उपयोग, श्रेष्ठ अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही विभागीय सिस्टम को नई तकनीक से जोड़ने और पेपरलेस करने की दिशा में कार्य दिया गया है। इसी तरह से खनिज क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने, अधिकारियों के रिओरियेंटेशन, खनन क्षेत्र से जुड़े स्टैक होल्डर्स व विभाग के बीच साझा मंच उपलब्ध कराने, देश दुनिया में तकनीक में आ रही बदलाव से रुबरु कराने सहित इस तरह के कार्यों के लिए कान्वल्वे, सेमिनार, संगोष्ठियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा व आयोजन का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार ने पीएमयू गठित कर जिम्मेदारी तय करने के साथ ही सरकार की ईच्छा शक्ति स्पष्ट कर दी है। अब पीएमयू टीम को जी जान से जुटते हुए माइनिंग के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनाने के लिए जुट जाना होगा। माइनिंग सेक्टर आज देश दुनिया में महत्वपूर्ण सेक्टर हो गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रोएक्टिव रोल अपनाने की पहल निश्चित रूप से समय की मांग के अनुकूल है। केन्द्र सरकार भी गंभीर है और क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों की नीलामी का काम तो केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। इसी तरह से केन्द्र सरकार ने मोनेट्रिंग सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही प्रोत्साहन के रूप में परफोरमेंस के आधार पर खानों की रेटिंग कर पुरस्कृत करने की पहल की है। जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को माहौल बना है। राजस्थान सरकार ने भी रेटिंग सिस्टम अरंभ करने की पहल की है।

वातावरण और पर्यावरण दिखावे से बचाव तक की यात्रा

बारिशें जब आशीर्वाद की तरह नहीं बल्कि कहर बनकर बरसती हैं, तो हमारी जिंदगी का असली चेहरा सामने आता है। शहरों की सड़कें, गलियाँ और नाले पानी से भर जाते हैं। प्रशासन पुराने ढर्रे में काम करता रहता है, जूनेज सिस्टम अस्त-व्यस्त हो चुका होता है, और आम आदमी मजबूरन परेशान होकर रह जाता है। लोग अपने घरों में पानी भरे कमरों में फँस जाते हैं, गाड़ियों को धकेलते हैं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इस बीच कई लोग, जिन्हें तैरना नहीं आता, अचानक ही तैराकी सीख जाते हैं, क्योंकि कभी की गहराई उन्हें मजबूर कर देती है। आपदा की इस स्थिति में अवसर खोजने वाले लोग हमेशा से मौजूद रहे हैं। आपदा के फायदा उठाने की परंपरा जीवन का हिस्सा बन गई है। शासन और प्रशासन बार-बार जिम्मेदार लोगों से अपील करता है, समाचार पत्र और सोशल मीडिया में चेतावनी दी जाती है, लेकिन समाज की प्रवृत्ति बदलती नहीं दिखती। "सामाजिक जानवर" यानी इंसान अक्सर अपने स्वार्थ और आराम के कारण पर्यावरण के प्रति लापरवाह रहता है। भाषण देने वाले बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि जंगल बचाकर और पेड़ लगाकर ही वातावरण और पर्यावरण सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन उनकी यह बात अक्सर हवा में ही खो जाती है। क्योंकि लोग पहले जैसी सभ्यता नहीं दिखाने। आजकल पर्यावरण के लिए रैलियों और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोग टी-शर्ट्स, दस्ताने, हरी टोपी और बड़े-बड़े बैनर लेकर इन आयोजनों में शामिल होते हैं। रैली के आयोजक इसे प्रतीकात्मक महत्त्व देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि रैली में शामिल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अवैध निर्माण कर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया हो। रैली के दौरान पानी की बोतलें, खाने-पीने के सामान और मोसमी फल जैसे सेब, केले आदि का भोग लगाना आम बात है। बहुत सारे पैसे सिर्फ दिखावे के लिए खर्च हो जाते हैं, जबकि पर्यावरण को वास्तविक रूप से नुकसान पहुँचाया हो। रैली के अंत में पर्यावरण और हरित भारत के लिए सुरक्षित और हरित भारत का आधार बनना।

अपेक्षा करना आसान होता है, लेकिन स्वयं अपने हिस्से का योगदान देना मुश्किल लगता है। यही वजह है कि प्रदूषण, प्लास्टिक और नाले पानी और जल संकट जैसी समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं के पास इस मामले में विशेष भूमिका है। घर में प्लास्टिक कम करना, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना, और पौधों की देखभाल करना आसान कदम हैं। प्लास्टिक के फूलों की जगह वास्तविक इनडोर पौधे रखना, मिट्टी के गमलों में पौधे लगाना, और सामान लाने के लिए कपड़े के थैले का प्रयोग करना बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं। दुकानदार से पैकड वस्तुएँ सीधे थैले में लेना, या पांच 'R' — रियूज, रिड्यूस, रियेयर, रिसाइकिल और रिकवर — को अपनाना, जीवन के पांच तत्वों — आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी — को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा योगदान है।

लेकिन असली चुनौती यह है कि यह आसान उपाय भी अक्सर कठिन लगते हैं। लोग अपने दैनिक जीवन की आदतों में बदलाव करने के बजाय दिखावे और बहानों का सहारा लेते हैं। आरामदायक बैडकों, लंबी रैलियों और बैनर मार्चों के माध्यम से वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का भ्रम पाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पर्यावरण संरक्षण दिखावे का परिणाम है। जब लोग यह समझेंगे कि उनके छोटे-छोटे कदम — पानी बचाना, प्लास्टिक कम करना, पौधे लगाना और उनके संरक्षण में सक्रिय होना — वास्तव में पर्यावरण की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, तभी हमारी बारिश, बाढ़ या गर्मी जैसी आपदाओं में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। आसान उपायों में ही स्थायी समाधान छिपा है। असल में, पर्यावरण और वातावरण की सुरक्षा सिर्फ बड़े-बड़े नारे लगाने या रैलियों करने आम बात है। बहुत सारे पैसे सिर्फ दिखावे के लिए खर्च हो जाते हैं, जबकि पर्यावरण को वास्तविक रूप से नुकसान पहुँचाया हो। रैली के अंत में पर्यावरण और हरित भारत के लिए सुरक्षित और हरित भारत का आधार बनना।

अभियान



सिद्ध मंत्र की शक्ति से राजा की मदिरा लत का अंत

बहुत समय पहले एक विद्वान राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका शासन प्रजा के लिए वरदान माना जाता था, परंतु धीरे-धीरे राजा एक ऐसी आदत में फँस गया जिसने उसके जीवन और राज्य दोनों को अंधकार में डकेल दिया — यह थी मदिरापान की बुरी लत। आरंभ में बह केवल उसवों या शिकार के अवसर पर मदिरा पीता था, परंतु धीरे-धीरे उसका मन उससे बंधता गया। अब वह बिना मदिरा किए रह ही नहीं सकता था। जैसे ही सूर्य उदरता, उसके महल में मदिरा के बड़े-बड़े प्याले सजाए जाते। राजा पीता, और उसके दरबारी उसकी खुशामद के लिए उससे भी अधिक पीकर राजा की प्रसन्नता अर्जित करने का प्रयत्न करते। यह देखकर दरबार के पुरोहित, ऋषि, विद्वान और धर्माचार्य अत्यंत दुखी हुए। वे समझते थे कि राजा के इस दुर्व्यसन से न केवल उसका स्वास्थ्य और विवेक नष्ट हो रहा है, बल्कि पूरा राज्य भी पतन की ओर जा रहा है। अनेक बार उन्होंने राजा को उपदेश दिया — धर्म का, संयम का, स्वास्थ्य का, किंतु जब किसी को अपने विषय में दोष सुनने की आदत नहीं होती, तब उपदेश अग्नि में घी डालने जैसा

बन जाता है। यही हुआ। राजा ने एक दिन क्रोध में आकर उन सभी विद्वानों, उपदेशकों और धर्माचार्यों को पकड़कर जेल में डाल दिया। उसने ऐलान किया कि अब से जो भी मदिरा के दोष बताएगा, उसे आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। अब राज्य में भय व्याप्त हो गया। कोई किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। दरबार में जो बात होती, वही कानून बन जाती। धीरे-धीरे प्रजा असंतुष्ट होने लगी, प्रशासन अस्त-व्यस्त हो गया और राज्य में अनाचार, अपराध तथा पीड़ा बढ़ने लगी। ठीक उसी समय एक दिन एक सिद्ध महात्मा उस राज्य में पधारे। उन्होंने देखा कि राजधानी के मार्गों पर नशे में झुमते सैनिक और अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, और धर्म की भावना विलुप्त हो चुकी है। महात्मा को ज्ञात हो गया कि जब तक इस राज्य के राजा का चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और एक अद्भुत उपाय सोचा। अगले दिन वे राजधानी के मुख्य चौक को अपने विषय में दोष सुनने की आदत नहीं होती, तब उपदेश अग्नि में घी डालने जैसा

आओ सुनो, कैसे मदिरा जीवन को आनंदमय बनाती है।" यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अब तक किसी ने सार्वजनिक रूप से मदिरा की प्रशंसा करने का साहस नहीं किया था। यह समाचार पलभर में राजमहल तक पहुँचा। राजा को जब पता चला कि कोई बाहरी महात्मा मदिरापान के गुण बता रहा है और कल वह मदिरा पीने की 'सुरक्षित विधि' भी सिखाने वाला है, तो राजा अंतर्मुख हो गया। वह सोचने लगा कि अब कोई महात्मा उसके पक्ष में भी तो बोले। अगले दिन राजा स्वयं अपने परिवार और मंत्रियों सहित उस महात्मा के चरणों में पहुँचा और विनम्र होकर कहा — "महाराज! कल का आपका व्याख्यान हमारे राजदरबार में हो, ताकि पूरी प्रजा आपके उपदेश से लाभान्वित हो।" महात्मा मुस्कुराए और बोले — "राजन! जैसा आपकी इच्छा।"

दूसरे दिन राजमहल में महात्मा का विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। सभी दरबारी, रानियें, सैनिक और प्रमुख नागरिक उपस्थित हुए। महात्मा ने कहा — "मद्यपान में दोष नहीं है, दोष तो मनुष्य की अज्ञानता में है। जैसे विष में भी औषधि छिपी होती है, वैसे ही यदि मदिरा को शुद्ध कर लिया जाए तो वह हानिकर नहीं रहती।" यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उत्सुक होकर बोला — "महाराज! कृपा करके वह शुद्ध करने की विधि बताइए जिससे हम भी सही रीति से मदिरा पान कर सकें।" "राजन! मदिरा शुद्ध तभी होती है जब उस पर एक सिद्ध मंत्र का प्रभाव पड़े। इसके लिए स्फटिक की माला पर चौबीस लाख बार उस मंत्र का जप करना आवश्यक है। जब माला सिद्ध हो जाए, तो उसके प्रत्येक दाने में वह शक्ति संचित रहती है। तब उस माला का एक दाना प्याले में डालकर मदिरा उड़ेलनी चाहिए। यदि दाना बीच में डूब जाए तो समझो कि वह शुद्ध हो गई। रोज एक नया दाना डालना चाहिए। जब सौ आठ दाने हो जाएँ, तब वह मदिरा पूर्ण रूप से शुद्ध कही जाएगी।"

राजा ने माथे पर हाथ रख लिया। वह बोला — "महाराज! यह तो बहुत लंबा उपाय है। चौबीस लाख मंत्र जप को मतीयों क्या, वर्षों में पूरे होंगे। तब तक मैं क्या करूँ? मैं तो एक दिन राजा ने माथे पर हाथ रख लिया। वह बोला — "महाराज! यह तो बहुत लंबा उपाय है। चौबीस लाख मंत्र जप को मतीयों क्या, वर्षों में पूरे होंगे। तब तक मैं क्या करूँ? मैं तो एक दिन महात्मा ने कहा — "मद्यपान में दोष नहीं है, दोष तो मनुष्य की अज्ञानता में है। जैसे विष में भी औषधि छिपी होती है, वैसे ही यदि मदिरा को शुद्ध कर लिया जाए तो वह हानिकर नहीं रहती।" यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उत्सुक होकर बोला — "महाराज! कृपा करके वह शुद्ध करने की विधि बताइए जिससे हम भी सही रीति से मदिरा पान कर सकें।" "राजन! मदिरा शुद्ध तभी होती है जब उस पर एक सिद्ध मंत्र का प्रभाव पड़े। इसके लिए स्फटिक की माला पर चौबीस लाख बार उस मंत्र का जप करना आवश्यक है। जब माला सिद्ध हो जाए, तो उसके प्रत्येक दाने में वह शक्ति संचित रहती है। तब उस माला का एक दाना प्याले में डालकर मदिरा उड़ेलनी चाहिए। यदि दाना बीच में डूब जाए तो समझो कि वह शुद्ध हो गई। रोज एक नया दाना डालना चाहिए। जब सौ आठ दाने हो जाएँ, तब वह मदिरा पूर्ण रूप से शुद्ध कही जाएगी।"

राजा ने प्रसन्नता से माला ले ली। उसी दिन उसने महात्मा के कहे अनुसार प्याले में एक दाना डालकर मदिरा पी ली। अगले दिन से उसने स्वयं मंत्र-जप आरंभ किया, क्योंकि उसे अपनी माला तैयार करनी थी। आरंभ में तो वह केवल विधि निभा रहा था, परंतु धीरे-धीरे उस जप में उसे एक अद्भुत शांति अनुभव होने लगी। जैसे-जैसे दाने बढ़ते गए, वैसे-वैसे उसका मन मदिरा से घटकर जप की ओर बढ़ता गया। एक दिन, जब लगभग सत्तर दाने प्याले में एकत्र हो चुके थे, तो अचानक उसके भीतर से एक विचार उठा — "यह क्या कर रहा हूँ मैं? इस मंत्र-जप में जो आनंद है, वह मदिरा में कहीं! यह तो आत्मा को नशे में भर देने वाला अमृत है।" यह विचार जैसे ही आया, राजा ने प्याला उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। उसने दरबार में घोषणा कर दी — "आज से राज्य में मदिरा पान पूर्णतः निषिद्ध है। जो भी मदिरा खेगा, वह धर्मदोही माना जाएगा।"

उसने आदेश दिया कि सभी मदिरा के सके नगर के गंदे नालों में बहा दिए जाएँ। इसके बाद उसने जेल में बंद सभी धर्माचार्यों, पुरोहितों और विद्वानों को मुक्त किया और उनसे क्षमा माँगी। उसने महात्मा के चरणों में जाकर कहा — "महाराज! आपने मुझे केवल मदिरा से नहीं, मेरे अंधकार से भी मुक्त कर दिया।" महात्मा मुस्कुराए और बोले — "राजन! मैंने कुछ नहीं किया। मंत्र न्यायप्रिय और योगाभिलाषी बन गया। राज्य में पुनः शांति और समृद्धि लौट आई। प्रजा महात्मा के इस अद्भुत उपाय की चर्चा वर्षों तक करती रही। यह कथा यह सिखाती है कि किसी की बुरी आदत केवल उपदेश से नहीं जाती, बल्कि जब उसे उससे भी ऊँचा आनंद मिल जाता है, तभी उसका मोह समाप्त होता है। महात्मा ने राजा की लत को नकारा नहीं, उसे रूपांतरित कर दिया। उन्होंने उसे दिखाया कि सच्चा नशा ईश्वर-स्मरण में है, न कि इद्रियों के विषयों में।

विकास सप्ताह : 13 अक्टूबर, शहरी विकास दिवस

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी गरीबों को दिए पक्के मकान, हर चेहरे पर खिल उठी मुस्कान

▶▶ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 9.09 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूर्ण
▶▶ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल कार्यान्वयन के लिए गुजरात को अब तक कुल 14 अवॉर्ड मिले

(जीएनएस)। गांधीनगर : 7 अक्टूबर, 2025 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 24 वर्ष पूरे हो गए हैं। विकास के इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाने के लिए हर साल 7 से 15 अक्टूबर के दौरान विकास सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 12 और 13 अक्टूबर शहरी विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2005 में शहरी विकास वर्ष मनाकर योजनाबद्ध शहरी विकास की आधारशिला रखी थी। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात शहरीकरण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विश्वस्तरीय शहरी विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार ने वर्ष 2025 को 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और निचले मध्यम वर्ग के परिवारों को उनके सपनों का घर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसी अहम योजना क्रियान्वित की है और आज, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात इस योजना के कार्यान्वयन में देश का अग्रणी राज्य है।

शहरी गरीबों को मिला उनके सपनों का घर, 9.09 लाख से अधिक घरों का हुआ निर्माण

जयपुर में हनीट्रैप गैंग का पर्दाफाश, अमीर लोगों को फंसा कर अश्लील वीडियो से करते थे ब्लैकमेल

जयपुर में मालवीय नगर थाना पुलिस ने एक बड़े हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो शहर में लंबे समय से सक्रिय था और अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य महिला आरोपी अभी फरार हैं। यह कार्रवाई जयपुर पुलिस की हालिया बड़ी उपलब्धियों में गिनी जा रही है, जिसने कई लोगों को ठगी और सामाजिक बदनामी के जाल से बचाया है।

एसीपी (मालवीय नगर) आदित्य पुनिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश कुमार बागड़ा (36 वर्ष) निवासी महावीर नगर और नीतू सोनी (39 वर्ष) निवासी कनकपुरा फाटक, करणी विहार शामिल हैं। वहीं, गिरोह से जुड़ी आरती शर्मा और दिव्या सोलंकी नामक दो महिलाएं फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार दक्षिण दे रही है। थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी मोदी ने नीतू के साथ मिलकर एक कॉललाग नेटवर्क तैयार किया था, जिसके जरिए वे पैसे वाले और प्रभावशाली लोगों को फंसाने की साजिश रचते थे। गिरोह का मुख्य ठिकाना महावीर नगर, दुर्गापुरा और करणी विहार क्षेत्र में स्थित किराए के मकान थे, जहां से यह गिरोह संचालित होता था। पुलिस के अनुसार, गिरोह पहले अपने टारगेट का चयन बहुत सोच-समझकर



करता था। वे सोशल मीडिया या व्यावसायिक नेटवर्किंग के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान करते थे जो धनवान हैं और जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो। इसके बाद गिरोह के सदस्य पहले दोस्ती करते, फिर उन्हें अपनी महिला सदस्यों से फोन पर बातचीत करवाते। धीरे-धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ाया जाता और फिर किसी होटल या प्लेट में मुलाकात करती जाती। मुलाकात के दौरान कमरे में गुप्त रूप से कैमरे लगाए जाते, जिनसे अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे। इसके बाद उन्हीं वीडियो और तस्वीरों को दिखाकर पीड़ितों को ब्लैकमेल किया जाता और उनसे लाखों रुपये वसूल जाते। कई बार ये गिरोह पीड़ितों की बदनामी के डर का फायदा उठाकर उन्हें दोबारा-तीसरी बार भी पैसों

के लिए धमकाता था। पुलिस की इस कार्रवाई में कोस्टेबल रामवतार और भरतलाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी सतर्कता और सूचना के आधार पर यह गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप और कैमरा उपकरण जब्त किए हैं, जिनमें कई संदिग्ध वीडियो और फोटो मिलने की संभावना है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और यह जांच कर रही है कि इस गिरोह के तार अन्य शहरों या राज्यों से तो नहीं जुड़े हैं। यह मामला जयपुर में बढ़ती अनलाइन ब्लैकमेलिंग और सोशल ट्रैफिंग अपराधों पर पुलिस की सख्त निगरानी का एक बड़ा उदाहरण बन गया है।

अमित शाह करेंगे जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और 4 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग, राजस्थान बनेगा विकास का नया केंद्र

जयपुर आज एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे सीतापुर स्थित जयपुर एजीबियन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन न केवल कानून व्यवस्था में औद्योगिक और सामाजिक विकास की नई कहानी भी लिखेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगी, जो देश में लागू हुए नए अपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सूचना संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — के सफल एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा रही है। इस प्रदर्शनी की थीम है 'नव विधान - न्याय की नई पहचान', जो कानून व्यवस्था में पारदर्शिता, तकनीकी उन्नति और जनता की भागीदारी को एक स्वरूप में प्रस्तुत करेगी।

अमित शाह इस अवसर पर राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सफिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़



रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। यह राजस्थान की औद्योगिक प्रगति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही शाह 9,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। सरकार की लोकहितकारी योजनाओं के अंतर्गत शाह विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपये और दूध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपये की राशि का ऑनलाइन हस्तान्तरण करेंगे। इसके

जन्ता को न्याय व्यवस्था से जोड़ने और कानून की भाषा को सरल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। छह दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में हर दिन एक विशेष विषय पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन, कानूनविद, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और सामाजिक संस्थाएं भाग लेंगी। 13 अक्टूबर को पुलिस कार्य में तकनीकी नवाचारों पर चर्चा होगी। 14 अक्टूबर को फॉरेंसिक विज्ञान और उसके उपयोग पर विशेष सत्र रखा गया है। 15 अक्टूबर को जेल प्रशासन से जुड़े सुधारों और मानवाधिकारों पर विमर्श होगा। 16 अक्टूबर को कानून विशेषज्ञों और विधि छात्रों के बीच संवाद होगा। 17 अक्टूबर को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की रोकथाम पर एनजीओ द्वारा सामाजिक जागरूकता सत्र होगा। 18 अक्टूबर को इस प्रदर्शनी का समापन समारोह भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। जयपुर में यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि कानून, तकनीक, निवेश और सामाजिक न्याय का संगम है। अमित शाह की उपस्थिति के साथ राजस्थान न केवल नए निवेश का द्वार खोलेंगे, बल्कि न्याय और विकास के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक नई मिसाल स्थापित करेंगे।

नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' के 44वें संस्करण का किया शुभारंभ, देशभर में फिटनेस की नई लहर

नई दिल्ली रविवार सुबह एक अनोखी और ऊर्जावान पहल का केंद्र बनी, जब केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राजधानी में आयोजित 'संडे ऑन साइकिल' के 44वें संस्करण का नेतृत्व किया। यह पहल नागरिकों के बीच फिटनेस, स्वस्थ जीवनशैली और निवारक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है और अब यह देशभर में एक जनांदोलन का रूप ले चुकी है।

इस बार के आयोजन में खास बात यह रही कि इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया। उन्होंने नागरिकों को संदेश दिया कि मोटापा, डायबिटीज, और हृदय रोग जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए साइकिल चलाना और नियमित व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में सभी आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया और साइकिल राइड का आनंद लिया। इस अवसर पर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पदक विजेता प्रवीण कुमार, सोमन राणा और शैलेश कुमार भी उपस्थित रहे। डॉ. मांडविया ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा,

ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में पिलपार्ट को दी कंपाउंडिंग की पेशकश, जर्माना भरकर निपटा सकती है मामला

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक पिलपार्ट एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के घेरे में है। ईडी ने पिलपार्ट को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से जुड़े मामले में कंपाउंडिंग प्रक्रिया का विकल्प दिया है, जिसके तहत कंपनी जर्माना अदा कर और अपनी गलती स्वीकार कर मामला बंद कर सकती है। यह प्रस्ताव कंपनियों को लंबी जांच और कानूनी कार्रवाई से राहत देने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने पिलपार्ट से स्पष्ट कहा है कि यदि वह अपनी गलती स्वीकार करती है और जर्माना भरती है, तो यह मामला कंपाउंडिंग नियमों के तहत निपटारा जा



“कोविड के कठिन समय में मैंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की निष्ठा और समर्पण को बहुत करीब से देखा। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान अमूल्य है। जब डॉक्टर स्वस्थ जीवन संदेश देते हैं, तो समाज उस पर विश्वास करता है। यही कारण है कि हम 'संडे ऑन साइकिल' के माध्यम से जनता को स्वास्थ्य और फिटनेस की दिशा में प्रेरित करना चाहते हैं।”

मांडविया ने यह भी कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव है। साइकिल चलाना एक सरल, सस्ता और प्रभावी व्यायाम है, जिसे हर नागरिक अपना सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। 'खेल मंत्रालय के अनुसार, 'संडे ऑन साइकिल' अब तक पूरे भारत के 10,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है, जिसमें लाखों नागरिकों ने हिस्सा लिया है। यह अभियान अब केवल साइकिल चलाने का कार्यक्रम

करने की दिशा में एक प्रयास है, बल्कि विदेशी निवेशकों को यह संदेश देने के लिए है। यह है कि भारत में कानून व्यवस्था का पालन अनिवार्य है। एक वरिष्ठ ई-कॉमर्स अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह कदम भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय

संघर्ष में भी महत्वपूर्ण को भी इस मुद्दे पर ईडी ने तलब किया था। अमेजन के प्रवक्ता ने कहा कि वे चल रही जांच पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ईडी को भेजे गए अन्य सवालों के जवाब भी फिलहाल लंबित हैं। इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ईडी की यह कार्रवाई न केवल भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर की पारदर्शिता सुनिश्चित

नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय फिटनेस मूवमेंट बन गया है। इस अवसर पर पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने कहा, “निर्धामित व्यायाम से व्यक्ति का ध्यान केन्द्रित रहता है और वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है। साइकिल चलाना इसका सबसे अच्छा तरीका है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।” वहीं शैलेश कुमार ने कहा, “सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। हमें रोजाना कम से कम एक घंटा अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। जनता का उत्साह देखकर स्पष्ट है कि फिटनेस अब लोगों की प्राथमिकता बन चुकी है।”

कार्यक्रम के अंत में डॉ. मांडविया ने कहा कि 'संडे ऑन साइकिल' केवल फिटनेस का प्रतीक नहीं, बल्कि यह सकारात्मक सोच, सामूहिक भागीदारी और स्वास्थ्य के प्रति जनजागरूकता का प्रतीक बन चुका है। इस पहल ने दिखाया है कि जब नागरिक, चिकित्सक और खिलाड़ी एक साथ स्वस्थ भारत के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो देश की ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों नए शिखर छूते हैं।

उल्लंघन को स्वीकार कर जर्माना भरने के बाद मामला समाप्त कर दिया जाता है। यह व्यवस्था कंपनियों को मुकदमेबाजी से बचाने के साथ-साथ सरकार को जर्माने के रूप में आर्थिक दंड प्रदान करने की अनुमति देती है। ईडी की जांच में यह सामने आया था कि पिलपार्ट और अमेजन इंडिया दोनों व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, “कंपाउंडिंग की व्यवस्था से कंपनियों को कानूनी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलती है और वे फेमा उल्लंघन स्वीकार कर जर्माना देकर मामला निपटा सकती हैं। इससे व्यापारिक माहौल स्थिर और पारदर्शी बनता है।” फेमा कानून के तहत कंपाउंडिंग एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी संस्था द्वारा किए गए

प्रेस्टीज गुप ने गाजियाबाद में 2,200 करोड़ रुपये मूल्य के 620 घरों की बिक्री शुरू की

नई दिल्ली। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लि. ने गाजियाबाद में 620 फ्लैटों की बिक्री शुरू कर दी है, जिससे कंपनी को लगभग 2,200 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व की उम्मीद है। यह पहल प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की मजबूत मांग के बीच अपने व्यापार का विस्तार करने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा है। इस वर्ष अप्रैल में बेंगलुरु की प्रेस्टीज एस्टेट्स ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 62.5 एकड़ में फैली टाउनशिप परियोजना शुरू करके दिल्ली-एनसीआर बाजार में प्रवेश किया था। अपनी टाउनशिप परियोजना 'द प्रेस्टीज सिटी, इंदिरापुरम' के पहले चरण में प्रेस्टीज एस्टेट्स ने ओकवुड और मलवरी नामक दो आवासीय परियोजनाएं शुरू की थीं, जिनमें 3,421 इकाइयां शामिल थीं, जिनका कुल बिक्री मूल्य लगभग 9,000 करोड़ रुपये था। कंपनी ने पहले चरण में पेश की गई लगभग सभी इकाइयां बेच दी हैं और अब दूसरे चरण 'मेफ्लावर' को पेश किया है, जिसमें 620 इकाइयां शामिल हैं। प्रेस्टीज गुप के वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (आवासीय), उठाते पर मजबूर कर देते हैं जो न केवल दो जीवन, बल्कि कई परिवारों को तबाह कर देते हैं। बेंगलुरु की यह घटना याद दिलाती है कि प्रेम, यदि विवेक और संवाद से न संभाला जाए, तो वह आग की तरह सब कुछ जला सकता है।

प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र महुड़ी जाना हुआ और भी आसान

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पिलवाई-महुड़ी फोरलेन रोड का किया लोकार्पण

▶▶ 20 करोड़ रुपये के खर्च से साढ़े चार किमी लंबी सड़क को सीमेंट-कंक्रीट फोरलेन में तब्दील किया
▶▶ दिवाली-काली चौदस के त्योहारों में महुड़ी दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन सुगम होगा
▶▶ मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य के सड़क नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने के लिए सीमेंट-कंक्रीट रोड निर्माण का सड़क एवं भवन विभाग का दृष्टिकोण

(जीएनएस)। गांधीनगर, 12 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र महुड़ी को पिलवाई से जोड़ने वाली 4.45 किलोमीटर लंबी फोरलेन सीमेंट-कंक्रीट सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क के निर्माण में 20 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस रोड के फोरलेन बनने से महुड़ी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही समय और ईंधन की बचत भी होगी। इतना ही नहीं, अहमदाबाद-गांधीनगर से विनापुर को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क के चौड़ीकरण के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सड़क एवं भवन विभाग को सेवा, समर्पण और सुशासन के 24 वर्ष

टिकाऊ बनाने के लिए दिए गए दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन के तहत विभाग ने सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों के निर्माण से जैसा कि 4.45 किलोमीटर लंबी फोरलेन सीमेंट-कंक्रीट सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क के निर्माण में 20 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस रोड के फोरलेन बनने से महुड़ी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही समय और ईंधन की बचत भी होगी। इतना ही नहीं, अहमदाबाद-गांधीनगर से विनापुर को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क के चौड़ीकरण के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा सड़क एवं भवन विभाग को सेवा, समर्पण और सुशासन के 24 वर्ष



पूरे होने और 25वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर 7 से 15 अक्टूबर के दौरान राज्यव्यापी विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। इस विकास सप्ताह में पूरे राज्य में अनेक कार्यक्रमों के लोकार्पण हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस विकास

सप्ताह के अंतर्गत महुड़ी-पिलवाई सड़क के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माणसा के विधायक श्री जे.एस. पटेल सहित कई पदाधिकारी, अग्रणी और गांव के नागरिक उपस्थित रहे।

बिहार चुनाव 2025: NDA में सीट बंटवारा हुआ तय, JDU और BJP को 101-101 सीटें, लोजपा, HAM और RLM को मिली हिस्सेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (NDA) में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सीट बंटवारे का मसला सुलझ गया। हफ्तों चली अंदरूनी बातचीत और खींचतान के बाद 'जेडीयू और बीजेपी दोनों को 101-101 सीटें, जबकि बाकी सीटें एनडीए के छोटे घटक दलों में बांटी गई हैं। इस सीट बंटवारे ने चुनावी तैयारियों में स्पष्टता ला दी है और सभी दलों ने मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत से फिर से सत्ता में लाने का संकल्प लिया है।

सीट बंटवारे का फॉर्मूला इस प्रकार है:

- जेडीयू (JDU): 101 सीटें
- बीजेपी (BJP): 101 सीटें
- लोजपा (रामविलास) [LJP(R)]: 29 सीटें
- रालोमो (RLM): 6 सीटें
- हम (HAM): 6 सीटें



जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सभी NDA घटक दलों ने

कर रहे हैं और मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में लाने के लिए तैयार हैं।

बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने भी सीट बंटवारे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सभी NDA घटक दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और जनता के सामने विकास और स्थिरता का चेहरा पेश करेंगे।

सीट बंटवारे के बाद अब सारा ध्यान उम्मीदवार सूची (Candidate List) पर केंद्रित है।

बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और दिल्ली में रविवार शाम होने वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक में अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इसके तुरंत बाद कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों के

नाम तय कर लिए हैं, बस सही समय का इंतजार है।

लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने भी घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी जल्द अपनी कैंडिडेट लिस्ट जारी करेगी।

इस तरह, बिहार में एनडीए की सीट बंटवारा प्रक्रिया पूरी हो गई है, और अब चुनावी तैयारियों में सभी दल कैंडिडेट फाइनेललाइजेशन और प्रचार अभियान पर जोर देंगे।

इस सीट बंटवारे में देखा जा सकता है कि चिराग पासवान की लोजपा को 29 सीटें, जबकि HAM और RLM को समान रूप से 6-6 सीटें दी गई हैं। यह बंटवारा NDA के संपूर्ण एकजुट फ्रंट को दर्शाता है और आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत वापसी की संभावना बढ़ाता है।

अलीगढ़ में धारदार हथियार से युवक की बेरहमी से हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार



घटना की सूचना मिलने पर थाना जहां पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने मुख्य आरोपी अशद खान समेत आठ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

जहां क्षेत्र में घटना के बाद दुकानों

के शटर बंद हो गए और इलाके में भय और तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने संवेदनशील स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी परिस्थिति में दोषियों को बख्शे जाने की अनुमति नहीं देने का संकल्प लिया है।

घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए पूरी कार्रवाई तेज कर दी है।

खिला प्रशासन और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के महत्व को फिर से रेखांकित करती है।

असम की जनसंख्या में बड़ा बदलाव, CM हिमंत बिस्वा सरमा का दावा: हिंदू आबादी घटकर 40%, मुस्लिम आबादी करीब 39.5%

(जीएनएस)। गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य की जनसंख्या में हो रहे बदलाव को लेकर रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि असम में हिंदुओं की आबादी अब कुल आबादी का लगभग 40 प्रतिशत रह गई है, जो मुस्लिम आबादी के लगभग बराबर है। मुख्यमंत्री ने इस बदलाव को "जनसांख्यिकीय परिवर्तन का बड़ा अंश" बताते हुए आगाह किया कि यदि अन्य समुदायों को अलग रखा जाए, तो असम में हिंदू आबादी अब 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2021 के अनुमानों के अनुसार, मुस्लिम आबादी अब राज्य की कुल आबादी का लगभग 39.5 प्रतिशत हो गई है, जबकि ईसाई आबादी 6-7 प्रतिशत के बीच है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े 2011 की जनगणना और उसके बाद के अनुमानों पर आधारित हैं। मुख्यमंत्री ने इस जनसांख्यिकीय बदलाव की मुख्य वजह अवैध घुसपैठ को बताया। उन्होंने कहा कि वैष्णव संस्कृति का केंद्र और दुनिया के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीप माजुली जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वृद्धि स्थानीय मुसलमानों की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि



के कारण नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठियों के कारण हुई।

सरमा ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित "जनसांख्यिकीय मिशन" का समर्थन करते हुए इसे इस मुद्दे के समाधान की दिशा में पहला निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर इस मिशन की घोषणा एक सकारात्मक पहल है, जो असम और अन्य प्रभावित राज्यों में संतुलित जनसंख्या सुनिश्चित करने में

मदद करेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार असम में हिंदुओं की आबादी लगभग 61.47 प्रतिशत थी, जबकि मुस्लिम आबादी में कहीं अधिक विवशनीय है। उन्होंने दावे इस समय सामने आए हैं जब असम में अवैध घुसपैठ और नागरिकता से जुड़े मुद्दे राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बने हुए हैं। इस बयान ने राज्य में जनसांख्यिकी और सामाजिक संरचना पर नई बहस को जन्म दिया है।

निवेशकों के लिए यह हमेशा एक सवाल रहा है कि अस्थिर आर्थिक दौर में पैसा कहाँ लगाया जाए—न्या ट्रेंडिशनल निवेश, जैसे सोना, या फिर मॉडर्न डिजिटल असेट, यानी क्रिप्टोकरेंसी। इस बहस में अब जोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर और 50 हजार करोड़ रुपए के मालिक श्रीधर वेन्मू ने अपना स्पष्ट रुख पेश किया है।

हाल के वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी ने निवेशकों को आकर्षक रिटर्न दिए हैं। बिटकॉइन ने बीते पांच साल में तीन गुना तक रिटर्न दिया है, वहीं सोने ने भी इसी अवधि में निवेशकों को करीब तीन गुना लाभ पहुंचाया है। हालांकि, मौजूदा साल में बिटकॉइन ने निवेशकों को केवल 30 प्रतिशत का मामूली रिटर्न दिया, जबकि सोने ने 50 प्रतिशत से अधिक की कमाई दी। ऐसे में सवाल उठता है कि बुरे वक्त में निवेशकों का असली साथी कौन है।

श्रीधर वेन्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर स्पष्ट किया कि उनके लिए लॉन टर्म वैल्यू और भरोसे के मामले में सोना क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि सोने को वह "गिरती करेंसी के मुकाबले में इंश्योरेंस" मानते हैं, यानी जब महंगाई बढ़ती है या पेपर करेंसी की वैल्यू गिरती है, सोना अपनी क्रय शक्ति बनाए रखता है। उनके अनुसार सोने ने दीर्घकालिक निवेशों जैसे सरकारी बॉन्ड



और ट्रेजर बिल्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं, क्रिप्टोकरेंसी के प्रति वेन्मू सतर्क हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्तियों में उन्हें कभी दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि ये अत्यधिक अप्रत्याशित हैं और मूल्य काफी हद तक सॉफ्टवेयर सिस्टम और सट्टा बाजार पर निर्भर करता है। उनका मानना है कि पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि इसे केवल केंद्रीय बैंकों या तकनीकी इंजीनियरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीधर वेन्मू की यह सोच भारतीय मानसिकता से भी मेल खाती

है, जहां सोना केवल निवेश का माध्यम नहीं बल्कि सुरक्षा और धन का प्रतीक है। परिवार अक्सर अनिश्चित समय में सोना खरीदकर अपनी बचत को सुरक्षित रखते हैं। ग्लोबल स्तर पर भी सोने की बढ़ती कीमतें इसे भरोसेमंद विकल्प बनाती हैं। इस प्रकार, डिजिटल फिनटेक और नई तकनीकों के बावजूद श्रीधर वेन्मू का संदेश साफ है—अनिश्चित आर्थिक दौर में रियल वैल्यू अभी भी उस चीज में है जिसे आप अपने पास रख सकते हैं, और इस दृष्टिकोण में सोना ही बुरे वक्त का असली साथी और हीरो बनकर उभरता है।

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराकर वनडे इतिहास का सबसे बड़ा चेज किया

विशाखापत्तनम। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-13 में ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हराया। यह मुकाबला विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मूटि मंधाना और प्रतीका की शानदार फिफ्टी के दम पर 331 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। लेकिन इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसे केवल 49 ओवर में ही हासिल कर लिया और वनडे महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चेज दंड किया।



जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका और अब ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। मंधाना और प्रतीका के शतकीय प्रदर्शन के बावजूद भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई

बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए और बड़ी जीत का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके। दूसरी ओर, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी का

प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने पहले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को पराजित किया था, जबकि श्रीलंका के खिलाफ उनका मैच धूल गया था। ऑस्ट्रेलिया की यह जीत उन्हें टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर बनाए रखने में मदद करेगी और साथ ही भारत के लिए आगामी मैचों में चुनौती बढ़ा दी है। विशाखापत्तनम के इस मुकाबले ने दर्शकों को रोमांचक अंत तक बांधे रखा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बड़े शांत खेलें और दबाव में भी कूल प्रदर्शन किया, जिससे यह चेज वनडे इतिहास में सबसे यादगार और सबसे बड़े चेज के रूप में दर्ज हो गया। भारतीय टीम अब अपनी रणनीति सुधारकर आगे के मैचों में वापसी करने की कोशिश करेगी।

अहमदाबाद में टोरेंट समूह के यूएनएम फाउंडेशन ने 'संकलन' नामक अत्याधुनिक न्यूरो पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की

अहमदाबाद। चिकित्सा और मानवता के संगम का प्रतीक बनते हुए टोरेंट समूह समर्थित यूएनएम फाउंडेशन ने रविवार को अहमदाबाद में देश के सबसे उन्नत न्यूरो पुनर्वास केंद्र 'संकलन' का शुभारंभ किया। लगभग 30,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला यह केंद्र स्ट्रोक, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की चोटों, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक समग्र उपचार केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।

फाउंडेशन ने बताया कि 'संकलन' का उद्देश्य विशेष रूप से वंचित और मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले मरीजों को किरायाती और वैज्ञानिक

पुनर्वास सुविधा प्रदान करना है। यह केंद्र विज्ञान, तकनीक और सहानुभूति के संयोजन पर आधारित है, जो मरीजों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पुनर्स्थापना के लिए व्यक्तिगत उपचार कार्यक्रम तैयार करता है।

केंद्र में फंक्शनल नियर-इन्फ़रमेटिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी (fNIRS), गैर-आक्रामक मस्तिष्क उत्तेजना प्रणाली, रोबोटिक पुनर्वास उपकरण, और वर्चुअल रियलिटी-आधारित थैरेपी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन तकनीकों की मदद से मरीजों के मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर समझा जा सकता है और उनके पुनर्वास की गति

को वैज्ञानिक रूप से बढ़ाया जा सकता है।

यूएनएम फाउंडेशन के स्वास्थ्य पहल प्रमुख डॉ. चैतन्य दत्त ने कहा, "इस केंद्र का नाम 'संकलन' इस विचार से प्रेरित है कि विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताएँ — न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथैरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थैरेपिस्ट — एकजुट होकर मरीज की संपूर्ण चिकित्सा में योगदान दें। यह वास्तव में बहुविषयक समन्वय का प्रतीक है।"

टोरेंट समूह की निदेशक जिनल मेहता ने इस अवसर पर कहा कि 'संकलन' सिर्फ एक केंद्र नहीं, बल्कि भारत में न्यूरो पुनर्वास की एक नई दृष्टि है।

उन्होंने बताया कि यह परियोजना प्रायोगिक रूप से अहमदाबाद में शुरू की गई है, और इसके परिणामों के आधार पर इसे सूट, चडोरा और राजकोट जैसे शहरों में, तथा बाद में देशभर में विस्तार देने की योजना है। मेहता ने कहा, "हमारा उद्देश्य केवल उपचार प्रदान करना नहीं है, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों को उम्मीद देना है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ लंबे समय तक चलने वाली और थकाने वाली होती हैं, इसलिए 'संकलन' जैसी पहल मरीजों को शारीरिक हानि नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाती है।" अहमदाबाद में इस केंद्र के उद्घाटन ने यह संकेत दिया है कि भारत अब

गुजरात में कपास किसानों के लिए आप का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी हिरासत में, पुलिस और सरकार पर तीखा आरोप

(जीएनएस)। अहमदाबाद/बोटाद। गुजरात में कपास किसानों के उचित मूल्य और उनके अधिकारों की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा बुलाई गई महापंचायत रविवार को नहीं हो सकी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को पुलिस ने बोटद पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया। इसुदान गढ़वी आप किसान सेल के नेता राजू करपड़ा के खिलाफ कार्रवाई और किसानों के हितों की रक्षा को लेकर बोटद में महापंचायत बुलाई थी।



इसुदान गढ़वी ने हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2027 के चुनावों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली कैंबिनेट में पूरी गुजरात पुलिस बल दी जाएगी। उन्होंने आपिंग लगाया कि बोटद के मार्केटिंग यार्ड में किसानों को उनकी कपास का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और व्यापारी गौली कपास के नाम पर भाव कमा रहे हैं।

महापंचायत में शामिल होने के लिए तैयार कई पार्टी नेता मौके पर नहीं पहुंच पाए। महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष श्रेया पटेल और यूथ विंग के प्रमुख त्रिवारा सोलंकी को

अधिकारों पर हमला कर रहे हैं और अगर सभी किसान सड़कों पर उतर आएँ तो भाव्य सरकार को कौन बचाएगा। इसुदान गढ़वी ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगत मान को गुजरात बुलाकर किसानों की आवाज को मजबूत करेगी। उनका संदेश स्पष्ट था कि AAP किसानों को उनका हक दिलाने तक पीछे नहीं हटेगी और राज्य में किसानों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।

भारत ने 2024-25 के विपणन सत्र में किया 7.75 लाख टन चीनी का निर्यात, जिबूती बाजार सबसे बड़ा आयातक देश

नई दिल्ली। भारत ने वैश्विक बाजार में अपनी मीठी उपस्थिति दर्ज कराते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के विपणन सत्र में अब तक 7.75 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। यह जानकारी ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (AISTA) ने रविवार को जारी एक रिपोर्ट में दी। रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्यात आंकड़ा फरवरी से सितंबर 2025 के बीच का है, जो दर्शाता है कि भारत की चीनी उद्योग वैश्विक मांग के अनुरूप स्थिर और प्रतिस्पर्धी बना हुआ है।

चीनी का विपणन सत्र भारत में हर वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने 20 जनवरी 2025 को कुल 10 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी, जिसमें से अब तक 7.75 लाख टन चीनी का निर्यात पूरा हो चुका है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय चीनी मिलें अपने लक्ष्यों के निर्धारित समय से पहले पूरा करने की दिशा में अग्रसर हैं।

AISTA की रिपोर्ट के अनुसार, निर्यात की गई चीनी में सफेद चीनी



का हिस्सा सबसे बड़ा रहा है, जो 6.13 लाख टन है। इसके बाद रिफाइन चीनी का निर्यात 1.04 लाख टन और कच्ची चीनी (Raw Sugar) का निर्यात 33,338 टन रहा है।

सबसे अधिक भारतीय चीनी अफ्रीकी देश जिबूती को भेजी गईं, जिसकी मात्रा 1.46 लाख टन रही। इसके



बाद सोमालिया को 1.35 लाख टन, श्रीलंका को 1.34 लाख टन और अफगानिस्तान को 75,533 टन चीनी का निर्यात किया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की चीनी निर्यात नीति अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई बाजारों में मजबूत पैठ बना रही है। चीनी व्यापार विशेषज्ञों का मानना है

कि वैश्विक बाजार में भारत की इस उपलब्धि के पीछे चीनी उत्पादन में स्थिरता, बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था और सरकार की समय पर निर्यात अनुमति प्रमुख कारण हैं। हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों ने यह भी संकेत दिया है कि आगामी महीनों में भारत को आंतरिक मांग, मानसून वर्षा के प्रभाव और एथेनॉल उत्पादन नीति जैसे कारकों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये देश के घरेलू चीनी भंडार और भविष्य के निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं।

AISTA ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया कि भारत की चीनी मिलें अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में अधिक सक्षम हो चुकी हैं, जिससे भारत का चीनी निर्यात केवल मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी मजबूत हुआ है। इस तरह, 2024-25 के विपणन सत्र में भारत का 7.75 लाख टन का निर्यात न केवल एक आर्थिक उपलब्धि है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय कृषि और उद्योग क्षेत्र विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की पूरी क्षमता रखता है।

गोमती केवल नदी नहीं, सांस्कृतिक चेतना और

जीवनधारा की प्रतीक : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 'गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन' की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पीलीभीत से गाजीपुर तक प्रवाहित गोमती केवल एक नदी नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और जीवनधारा की प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमती का पुनर्जीवन सिर्फ जल शुद्धिकरण नहीं, बल्कि पर्यावरण, संस्कृति और समाज के पुनर्संरचना का व्यापक अभियान है। मुख्यमंत्री योगी टैरिगोरियल आर्मी की पहल पर आयोजित गोमती टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की सहभागिता से चलने वाला जन-आंदोलन होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोमती में एक भी बूंद सीवरज न गिरे, इसके लिए अत्यंतकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियाँ बनाई जाएँ। चीनी निर्यात केवल मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता में भी मजबूत हुआ है। इस तरह, 2024-25 के विपणन सत्र में भारत का 7.75 लाख टन का निर्यात न केवल एक आर्थिक उपलब्धि है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय कृषि और उद्योग क्षेत्र विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की पूरी क्षमता रखता है।